लोकतंत्र की आत्मा है - संवाद

हरियाणा संवाद

पाक्षिक 1 - 15 नवंबर 2022 www.haryanasamvad.gov.in अंक -53

"शुभम् करोति कल्याणम् आरोग्यम् धन संपदा। शत्रु वृद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते।'

हरियाणा सरकार के आठ साल, सुशासन के साथ चला प्रगति काल 2

मधुमक्खी पालन से युवाओं को मिला रोज़गार 6

नानक तेरा-तेरा 7

मनोहर काल में हुआ सर्वांगीण विकास

आठ वर्ष के कार्यकाल पर अमित शाह बोले, पीएम मोदी व सीएम मनोहर ने हरियाणा को बनाया नंबर वन

विशेष प्रतिनिधि

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा सरकार के 8 साल पूरा होने पर हरियाणा की जनता को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मनोहर लाल ने 8 साल का कार्यकाल बहुत यशस्वी तरीके से पूरा किया। मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने 8 साल में हरियाणा को बदलने का काम किया है। इस काल में प्रदेश का चहुंमुखी विकास हुआ है।

शाह बोले आजादी के बहुत समय के बाद पूरे हरियाणा को मनोहर लाल के रूप में एक मुख्यमंत्री मिला है। इससे पहले मुख्यमंत्री सिरसा या रोहतक के होते थे, पूरे हरियाणा के नहीं होते थे। हमारा मनोहर लाल पूरे हरियाणा का मुख्यमंत्री है।

अमित शाह ने कहा कि 8 साल पहले का हरियाणा याद करें तो एक सरकार में भ्रष्टाचार होता था तो दूसरी सरकार में गुंडागिरी। इस सरकार ने भ्रष्टाचार और गुंडागिरी को खत्म किया और ईमानदारी के साथ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए हरियाणा को शिखर तक पहुंचाने का काम किया। उन्होंने कहा कि मनोहर लाल ने सभी वर्गों की चिंता की है। अमित शाह ने पिछली सरकारों से तुलना करते हुए कहा कि 50 साल की सरकारें एक ओर तथा 8 साल की हमारी सरकार एक ओर, पलड़ा हमारा भारी है।

इस दौरान केंद्रीय गृहमंत्री ने पिछले 8 साल में हरियाणा सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया और मुख्यमंत्री सहित उनकी पूरी टीम को शाबाशी दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा पहला राज्य है जो धुंआ मुक्त बना है। हरियाणा में हर घर में गैस का चूल्हा है। खाद्यान्न और दुग्ध उत्पादन में हरियाणा दूसरे स्थान पर है। नेशनल गेम्स और ओलंपिक में हरियाणा पहले स्थान पर रहा है। हरियाणा देश का पहला पढ़ी लिखी पंचायतों वाला राज्य बना है। पूरा हरियाणा खुले में शौच मुक्त है। 6 प्रतिशत से अधिक की विकास दर के साथ हरियाणा हर क्षेत्र में आगे रहा है। मैन्युफैक्चरिंग की विकास दर तो 10 प्रतिशत रही है। अमित शाह ने कहा कि 10 साल पहले सॉफ्टवेयर निर्यात में हरियाणा का नाम तक नहीं था लेकिन आज हरियाणा दूसरे नंबर का राज्य बना है। सड़क पर चलने वाली हर दूसरी गाड़ी हरियाणा में बनती है।

अमित शाह ने कहा कि पिछले 8 सालों में हरियाणा में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। हरियाणा में विश्व की 400 फॉर्च्यून कंपनियां काम कर रही हैं। प्रदेश सरकार ने गुरुग्राम को उद्योग का हब बनाने का काम किया है। 8 साल पहले हरियाणा निर्यात में 16वें स्थान पर था लेकिन अब सातवें नंबर पर है, लैंडलॉक श्रेणी में तो हरियाणा देश में दूसरे नंबर पर है। हरियाणा सरकार ने पिछले 8 वर्षों में 98000 लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया है।

प्रगति में पूरा सहयोग देगा हरियाणाः सीएम

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। हमारी सरकार ने पिछले 8 सालों में व्यवस्था परिवर्तन करने का काम किया है, लोगों को ऑनलाइन तरीके से योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। वहीं पूरे प्रदेश में नेशनल हाइवे और रेल लाइन का जाल बिछाया है। शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य क्षेत्रों में हरियाणा सरकार ने बेहतर काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने गांव में 24 घंटे बिजली देने का काम किया। पिछली सरकारों के काल से तुलना करें तो इस सरकार के 8 साल भारी पड़ेंगे। हरियाणा पहला राज्य है, जहां पढ़ी-लिखी पंचायतें हैं।

मनोहर सौगात से बदलेगा भविष्यः रेल मंत्री

केंद्रीय रेल एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज पवित्र दिन है जब डबल इंजन की सरकार 8 वर्ष पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि गृहमंत्री ने हरियाणा को बहुत बड़ी सौगात दी है। इससे हरियाणा का भविष्य बदलेगा। रेल कोच नवीनीकरण कारखाना से बहुत बड़ा इको सिस्टम तैयार होगा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के समय में हरियाणा में रेल के विकास के लिए महज 315 करोड़ की राशि आवंटित की जाती थी लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में एक हजार चार सौ करोड़ का सालाना आवंटन हरियाणा में रेल के विकास के लिए किया जाता है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हरियाणा में रेलवे प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम चल रहा है। रेलवे ने हरियाणा के सात स्टेशनों का कंपलीट रिडवलपमेंट सेंक्शन किया है। फरीदाबाद में 262 करोड़ की लागत से वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का टेंडर फाइनल हो गया है, इसी तरह से गुरुग्राम, चंडीगढ़, अंबाला कैंट, करनाल, कुरुक्षेत्र और पानीपत में वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने के मास्टर प्लान की तैयारी है।

सम्मान और खजाना दोनों सुरक्षितः कृष्णपाल

केंद्रीय बिजली और भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि जहां-जहां बीजेपी की सरकार है वहां-वहां सुशासन और विकास है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में देश का सम्मान और खजाना दोनों सुरक्षित हैं तथा देश की सीमाएं भी सुरक्षित हैं।

प्रगति के विजन को साकार कियाः चौटाला

उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 3 साल पहले हरियाणा में भाजपा-जजपा की गठबंधन की सरकार बनी थी और इन 3 सालों में हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत की प्रगति के सपने व विजन को हरियाणा में पूरी तरह से साकार किया है और जन उत्थान करने का काम किया है।

परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने फरीदाबाद में आयोजित कार्यक्रम में 6,600 करोड़ रुपए से अधिक लागत की चार परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। अमित शाह ने लगभग 5,618 करोड़ रुपए लागत की हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास, सोनीपत जिला के बड़ी में बने 590 करोड़ रुपये लागत के रेल कोच नवीनीकरण कारखाने का उद्घाटन किया। उन्होंने 315 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से रोहतक में बने देश के पहले सबसे लंबे एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का लोकार्पण किया तथा भोंडसी में 106 करोड़ रुपए की लागत के हरियाणा पुलिस आवास परिसर का उद्घाटन किया। पुलिस आवासीय परिसर में 576 पुलिस परिवार रह सकेंगे।

केंद्र का सहयोग करना राज्यों का दायित्व

सुरजकुंड में आयोजित गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज वैश्विक स्तर पर भारत जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है उतनी तेजी से चुनौतियां भी आगे बढ़ने वाली हैं। विश्व की बहुत सारी ताकतें नहीं चाहेंगी कि भारत और अधिक सामर्थ्यवान बने। उन्होंने कहा कि केंद्र की एजेंसियों को एक साथ कई राज्यों में कार्य करने होते हैं। ऐसे में राज्यों का दायित्व बनता है कि वे सहयोग करें। श्री मोदी ने शिविर में 'वन नेशन वन यूनिफॉर्म' का सुझाव दिया और कहा कि सभी राज्य मिलकर काम करें ताकि चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला किया जा सके।

आज़ादी का अमृत महोत्सव

हरियाणा दिवस

कुछ तो है यहां की माटी में

हरियाणा प्रदेश का आज पूरे विश्व में डंका बज रहा है। खेल, शिक्षा, उद्योग, पर्यटन, कृषि, रोजगार, कला एवं संस्कृति आदि क्षेत्रों में हुई प्रगति सात समंदर पार बैठे लोगों की जिज्ञासा का विषय बनी हैं।

स्वास्थ्य, बिजली, विदेशी निवेश, सड़क-यातायात, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, राजकीय कामकाज में पारदर्शिता आदि अनेक क्षेत्रों में जिस गति से विकास हुआ है। उसे लेकर अन्य राज्यों में कौतूहल बना है कि कृषि प्रधान कहे जाने वाले हरियाणा प्रदेश में इतना सबकुछ कैसे?

गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के प्रयासों से गीता का आलोक विश्व के विभिन्न कोनों में पहुंच रहा है। युवा पीढ़ी को ज्ञात हो रहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने जिस कुरुक्षेत्र भूमि से गीता का 'अमर उपदेश' दिया था वह भूमि भी हरियाणा में है।

उल्लेखनीय है कि देश विदेश से बहुत सारे प्रतिनिधिमंडल मौजूदा राज्य सरकार द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं को जानने व समझने के लिए आ रहे हैं। 'खेलो इंडिया' कार्यक्रम में कुछ ऐसे अधिकारी, कोच एवं खिलाड़ी यह जानने का प्रयास करते नजर आए कि हरियाणा के खिलाड़ियों का खान पान क्या है? सरकार की ओर से किस प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं?

सूबे में व्यवस्था परिवर्तन के साथ पढ़ने-लिखने का माहौल बना है तो शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रतिभाएं निकल कर आ रही हैं। चिकित्सा, इंजीनियरिंग व अन्य संकायों में यहां के युवाओं ने विश्व स्तर पर अपनी पहचान व जगह बनाई है।

केंद्र सरकार के सहयोग से हड़प्पाकालीन सभ्यता के बड़े केंद्र राखी गढ़ी को हैरिटेज के तौर पर विकसित करने की योजना पर कार्य शुरू हो चुका है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र के बावन कोसिय बिंदूओं ने भी पर्यटकों को आकर्षित करने का काम किया है।

कुछ तो है यहां की माटी में। इस माटी की उर्वरा शक्ति जानने के लिए लोगों ने हरियाणा प्रदेश का रुख किया है। कोई उद्योग लगाने के लिए आ रहा है तो कोई आध्यात्मिक विकास के दृष्टिगत पर्यटक बन कर आ रहा है। कुल मिलाकर पिछले कुछ अर्से से बाहरी लोगों में हरियाणा के बारे में जानने की दिलचस्पी बढ़ी है। ऐसा भी है कि इस भूखंड पर जो एक बार आ जाता है उसका लौटने को दिल नहीं करता।

- मनोज प्रभाकर

संपादकीय

8 वर्ष, 56 वर्षों पर भारी

इसमें कोई संदेह नहीं कि गत आठ वर्ष का मनोहर-शासन पिछले 56 वर्षों पर भारी है। पूरी संकल्पबद्धता के साथ इस सरकार ने '3-सी' पर कड़ा प्रहार किया है। ये 3-सी हैं 'करप्शन, 'क्राइम' और 'कास्ट'। इसी क्रम में सरकार 5-एस अर्थात् शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलम्बन पर जोर दे रही है।

इस सरकार ने आईटी-आधारित सिस्टम बनाए हैं। परिवार-पहचान-पत्र ऐसी ही महत्वाकांक्षी परियोजना है, इसके माध्यम से गरीब परिवारों की पहचान कर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया गया है। किसानों की सहायता के लिए 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' बनाया गया है। ऑनलाइन स्थानांतरण नीति बनाई है। अब स्थानांतरण के लिए सिफारिशें नहीं आती, सभी का स्थानांतरण पारदर्शी तरीके से होता है। इसके अलावा प्रदेश में सामान्य सेवा केंद्र खोले गए हैं, जिनके माध्यम से आमजन को सरकारी योजनाओं व सुविधाओं का लाभ सुगमता से मिला रहा है। वर्तमान राज्य सरकार ने इन आठ सालों में व्यवस्था परिवर्तन के कार्य किए हैं। पिछली सरकारों ने गांवों को 24 घंटे बिजली देने की सिर्फ बात की, लेकिन यह सरकार आज गांवों में 24 घंटे बिजली दे रही है।

विशेष उपलब्धि यह रही है कि इस सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के 'विज़न' को प्रदेश में पूरी तरह से साकार किया है। 'कोरोना' के बावजूद प्रदेश कई आयामों में अग्रणी रहा। धान की खरीद के 9 हजार करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से 72 घंटों के अंदर सीधे किसानों के बैंक खातों में डाले गए हैं।

बायोमीट्रिक रिकॉग्निशन के साथ-साथ अब वॉयस रिकॉग्निशन पर भी काम किया जा रहा है ताकि अपराधियों की गिरफ्तारी व उन्हें सजा दिलाने के कार्य में भी आसानी हो। सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते इस्तेमाल से कानून व्यवस्था के समक्ष आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार का यह एक सराहनीय प्रयास है।

-डॉ. चन्द्र त्रिखा

133 सरपंच व 17158 पंच सर्वसमति से निर्वाचित

हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के प्रथम चरण के चुनाव में सम्मिलित 9 जिलों में 133 सरपंच तथा 17,158 पंच सर्वसम्मति से चुने गए हैं। सर्वसम्मति से चुने गए पंचों में 8,708 पुरुष एवं 8,450 महिलाएं हैं।

उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में 133 सरपंच सर्वसम्मति से चुने गये जिसमें से 74 पुरुष एवम 59 महिला शामिल हैं।

गौरतलब है कि प्रथम चरण में 2,607 पंचायतों में से सरपंच पद के चुनाव के लिए 17,597 उम्मीदवारों ने नामांकन किया और अब 11,391 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमे 6,044 पुरूष एवं 5,347 महिलाएं शामिल है ।

धनपत सिंह ने बताया कि पंचायत समिति के लिए 56 उम्मीदवार सर्वसम्मति से चुन लिए गए हैं जिसमें 25 पुरूष व 31 महिलाएं शामिल हैं। पंचायत समिति सदस्यों के 1,278 पदों के लिए 3,540 पुरुष एवं 2,596 महिलाओं सहित कुल 6,136 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा। अब 4,894 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, इनमें 2,821 पुरूष व 2,073 महिलाएं शामिल हैं।

जिला परिषद के 175 सदस्यों के लिए 1,590 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा और अब 1,254 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। जिला परिषद के लिए 717 पुरुष एवं 537 महिलाएं चुनाव लड़ रही है।

दूसरे चरण का मतदान नौ व 12 नवंबर को तथा तीसरे चरण का मतदान 22 व 25 नवंबर को होगा।

प्रदेश के सभी जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों के नतीजे 27 नवम्बर को घोषित किए जाएंगे। पंच व सरपंचों के चुनाव परिणाम उसी दिन घोषित किए जाएंगे।

धनपत सिंह ने प्रदेश के मतदाताओं से अपील की कि वे पंचायती राज चुनावों में बढ़चढ़ कर हिस्सा लें तथा ईमानदार एवं साफ सुथरी छवि के उम्मीदवारों को जिताएं। उन्होंने यह भी अपील की कि मतदाता जाति, धर्म आदि से ऊपर ऊठकर मतदान करें।

उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यता

» पंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं व अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवार के लिए 5वीं कक्षा पास होना जरूरी है।

» सरपंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए (जिसमें अनुसूचित जाति की महिला भी शामिल है) 8वीं पास होना जरूरी है।

» पंचायत समिति सदस्य के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं पास होना जरूरी है।

» जिला परिषद सदस्य के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं पास होना जरूरी है।

-संवाद ब्यूरो

पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, 2022 में हरियाणा शीर्ष पर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा लगातार बुलंदियों को छू रहा है। इसी का नतीजा है कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, 2022 में हरियाणा बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर आया है। इस रिपोर्ट में हरियाणा सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय एवं राजनीतिक न्याय में सबसे आगे रहा है। 0.6948 स्कोर के साथ हरियाणा ने बड़े राज्यों में पहले स्थान हासिल किया है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार जताया है और कहा कि उनके मार्गदर्शन में की वजह से ही यह संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश-प्रदेश में प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक व सकारात्मक बदलाव आया है।

सार्वजनिक मामलों के सूचकांक (पीएआई) 2022 की रिपोर्ट में हरियाणा के बाद तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, पंजाब और कर्नाटक सहित कई अन्य राज्य शामिल है। इसी रिपोर्ट में सिक्किम ने भारत में सबसे अच्छे शासित छोटे राज्य के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। बेंगलुरु के गैर-लाभकारी थिंक टैंक पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा तैयार पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, 2022 के 7वें संस्करण को जारी किया गया। इस रिपोर्ट में आर्थिक न्याय को श्रमिक उत्पादन, कार्मिक मजदूरी, पब्लिक एक्सपेंडिचर, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार जैसे पहलुओं पर मापा गया। वहीं ग्रामीण एवं निकाय संस्था, घटते अपराध, आम जनता के समस्याओं का निवारण राजनीतिक न्याय के घटक रहे।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा पीएआई इंडेक्स 2022 में पहले पायदान पर पहुंचा है, इसके लिए वे सभी को बधाई देते हैं। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के सही क्रियान्वयन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार मज़बूती के साथ चलते हुए अंत्योदय की भावना के साथ आमजन के सपनों को साकार कर रही है। आज समाज के हर एक तबके को बिना भेदभाव सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है।

- संवाद ब्यूरो

सलाहकार संपादक : डा. चंद्र त्रिखा
सह संपादक : मनोज प्रभाकर
स्टाफ राइटर : संगीता शर्मा
संपादन सहायक : सुरेंद्र बांसल
चित्रांकन एवं डिज़ाइन : गुरप्रीत सिंह
डिजिटल सपोर्ट : विकास डांगी

भारतीय उत्पादों की विदेशी बाजार में संभावनाएं

विभिन्न देशों में नियुक्त भारत के हाई कमिश्नर और राजदूतों ने भारतीय उत्पादों की विदेशी बाजार में मांग व पकड़ बनाने पर मंथन किया। राई औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगपतियों के साथ विशेष रूप से टेक्सटाइल्स क्षेत्र में विदेशों में निर्यात को बढ़ावा देने पर विचार-विमर्श किया गया।

चीन में नियुक्त भारतीय राजदूत प्रदीप कुमार रावत ने कहा कि अब करोड़ों रुपए की बजाय मिलियन और डॉलर्स में सोचना प्रारंभ करें। क्या कारण है कि हम चीन की ओर देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीन में कीमतों में दस गुणा वृद्धि के बावजूद विश्व स्तर पर बाजार पर उनकी मांग व पकड़ बनी हुई है। चीनी बाजार भारतीय उद्योगों को चुनौती देता है। हमने उपलब्धि हासिल की है किंतु मंजिल अभी दूर है। हमें 2 से 200 और 200 से 2000 करने की दिशा में सोचना होगा। इसके लिए उद्योगपति रोडमैप तैयार कर सरकार के समक्ष प्रस्तुत करें कि सरकार किस प्रकार से उनकी सहायता कर सकती है ताकि उनका व्यापार बढ़ सके।

इटली को भारत दे सकता है बेहतरीन विकल्प

इटली में भारत की राजदूत डा. नीना मल्होत्रा ने कहा कि पैकेजिंग क्षेत्र के लिए इटली अधिकतर वस्तुएं चीन से मंगवाता है। किंतु अब हालात बदल रहे हैं और इटली को चीन के विकल्प की तलाश है। ऐसे में इटली को भारत बेहतरीन विकल्प दे सकता है। इटली अब भारत की ओर देख रहा है, जिसके लिए हमें तैयार होना होगा। इटली बड़ा उत्पादक देश है जो भारत में निवेश भी कर सकता है। इटली की डिजाइनिंग क्षेत्र में मास्टरी है और भारत की टैक्सटाईल्ज में पहचान है। ऐसे में हमारी टैक्स्टाईल व इटली की डिजायनिंग का मिलान संभव है, जिससे भारतीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए गुणवत्ता पर हमें विशेष ध्यान देना होगा।

डेनमार्क में गुणवत्तापरक कपड़ों की मांग

डेनमार्क में भारतीय राजदूत पूजा कपूर ने कहा कि डेनमार्क व हरियाणा में एक समानता है कि दोनों ही क्षेत्र के मामले में लगभग बराबर दिखाई देते हैं किंतु टैक्सटाईल्ज के मामले में डेनमार्क बहुत आगे है। डेनमार्क में गुणवत्तापरक कपड़ों की मांग रहती है जिसे पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए। पैकेजिंग भी बेहतरीन होनी चाहिए जिसका पर्यावरण के साथ तालमेल बैठे। उन्होंने राई के उद्योगपतियों को डेनमार्क में होने वाले विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कार्य मों का निमंत्रण भी दिया।

पराग्वे के लोगों की चाहत भारत के साथ व्यापार

पराग्वे में भारत के राजदूत योगेंद्र सांगवान ने कहा कि पराग्वे में भारत के लिए अच्छी संभावनाएं हैं। भारत की वहां अच्छी प्रतिष्ठा है। ऐसे में पराग्वे के लोग भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें प्रयासों को गति देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत के उद्योगपतियों के प्रतिनिधिमंडल को पराग्वे का दौरा करना चाहिए, ताकि मिलकर व्यापार को बढ़ावा देने पर विचार किया जा सके।

जांबिया पर विशेष फोकस करें उद्योगपति

जांबिया में नियुक्त भारत के हाई कमिश्नर अशोक कुमार ने कहा कि जांबिया में टैक्सटाईल्ज के लिए संभावनाओं की कोई कमी नहीं है। भारत के टैक्सटाईल्ज उद्योगपतियों को जांबिया पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि वहां खुद का उत्पादन बहुत कम है। अधिकांश माल बाहर से ही मंगाया जाता है। भारतीय उद्योगपति जांबिया के क्षेत्रीय बाजार का पूर्ण लाभ उठा सकते हैं। वहां ट्रेड फेयर भी लगता है जिसमें हिस्सा लेना चाहिए।

कांगो में निर्यात की अपार संभावनाएं

कांगो में भारत के राजदूत रामकरण वर्मा ने कहा कि कोंगों में भारत के लिए निर्यात की अपार संभावनाएं हैं। कांगो में एक बड़ी आबादी गरीबी की श्रेणी में आती है। वहां बिजली की किल्लत है। ऐसे में सस्ती दरों के उत्पादों की वहां मार्केट बनाई जा सकती है। खनन व दवाइयों के क्षेत्र में भी बहुत संभावनाएं हैं। करीब 70 प्रतिशत दवाई भारत से जाती है। टेक्सटाईल्स के लिए भी बड़े बाजार के रूप में कांगो मौजूद है।

सिविल सचिवालय और चंडीगढ़ व पंचकूला में विभागों के मुख्यालयों में प्रत्येक मंगलवार को 'नो मिटिंग डे' घोषित किया गया है। इस संबंध में राज्य के सभी विभागाध्यक्षों व उपायुक्तों को पत्र जारी किया है।

राज्य सरकार ने उन औद्योगिक इकाईयों को मूल्य संवर्धन कर में 50 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है, जो अपनी ऊर्जा की आवश्यकता डीजल से चलने वाले जनरेटर सेट की बज़ाय नेचुरल गैस से पूरा करेंगी।

हरियाणा सरकार के आठ साल
सुशासन के साथ चला प्रगति काल

सुशासन ही आधार
डबल इंजन हरियाणा सरकार

साल राख्या ख्याल

मनोहर सरकार के आठ साल के कार्यकाल में प्रदेश का चहुंमुखी विकास हुआ है, वह भी बिना किसी भेदभाव के। मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच व साफगोई ने पूरे प्रदेश की कायापलट करने का काम किया है जिसके चलते लोगों का सरकार के प्रति विश्वास और सुदृढ़ हुआ है।

मनोहर सरकार की अनेक ऐसी उपलब्धियां हैं, जिनका शब्दों में वर्णन करना सहज नहीं है। कहना गलत न होगा कि बहुत सारी जन कल्याणकारी नीतियों ने शासन करने के मायने ही बदल डाले हैं। कुछ एक योजनाओं का जिक्र करें तो उनमें राजकीय कामकाज को पारदर्शी बनाने के लिए लागू की गई नीतियां हैं।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विगत सप्ताह दिल्ली हरियाणा भावन में सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा सरकार की उपलब्धियों पर संकलित पुस्तिका का लोकार्पण भी किया। उन्होंने इस मौके पर कुछेक योजनाओं का प्रमुखता से जिक्र किया।

जन कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और सेवाओं की कवरेज एक ही मंच से करने के लिए फैमिली आईडी यानि परिवार पहचान पत्र योजना लागू की गई है। इसके साथ सभी सरकारी योजनाओं और सेवाओं को जोड़ा जा रहा है। वृद्धावस्था सम्मान भत्ते को परिवार पहचान-पत्र के साथ जोड़ दिया है। अब व्यक्ति की आयु 60 वर्ष की होने पर उसकी वृद्धावस्था पेंशन खुद ब खुद लग जाती है। पीले राशन कार्ड बनाने का काम भी परिवार पहचान पत्र के माध्यम से किया जा रहा है। जिला सिरसा व कुरुक्षेत्र में यह योजना पायलट आधार पर शुरू की जा चुकी है।

न्यूनतम वार्षिक आय बढ़ाने का लक्ष्य

अंत्योदय 'मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान अभियान' के प्रथम चरण में सबसे गरीब 2 लाख परिवारों की पहचान करके उनकी न्यूनतम वार्षिक आय एक लाख रुपए करने का लक्ष्य रखा गया है। अधिक परिवारों को लाभ देने के लिए बीपीएल की वार्षिक आय सीमा 1.20 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपए की है। इस अभियान में सबसे पहले सबसे गरीब व्यक्ति का उत्थान करने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक प्रदेश में अंत्योदय उत्थान मेलों के तीन चरणों 33 हजार से अधिक गरीब परिवारों को स्वरोज़गार के लिए ऋण और निजी क्षेत्र में नौकरियां दिए गए हैं।

किसान हित में सरकार के कदम

राज्य सरकार ने 'मेरी फसल-मेरा ब्यौरा' वैब पोर्टल बनाया है। इस पर किसान अपने द्वारा बोई गई फसल और खेत का ब्यौरा घर बैठे भर सकते हैं। ऐसा करने से उनको अपनी फसल को बेचने या इसके ख़राब होने पर मुआवज़ा लेने के लिए सरकारी दफ्तरों और कर्मचारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और आने वाली फसलों के लिए खाद, बीज, ऋण और कृषि उपकरणों के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता भी घर बैठे मिल सकेगी। इस पोर्टल पर रबी व खरीफ सीजन में लगभग 9 लाख किसान पंजीकरण करवाते हैं।

योजनाएं ऑनलाइन

ऑनलाइन सेवाएं व्यवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया में 'सरकार कम से कम-सुशासन अधिकतम' के भाव से सरकारी लाभ देने में मानवीय हस्तक्षेप को कम करने के लिए अंत्योदय सरल पोर्टल पर 42 विभागों की 572 सेवाएं और योजनाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। अकेले 12 लाख शिकायत

सीएम विंडो पर मिलीं, जिसमें से 90 फीसदी का निपटारा किया गया। ऑनलाइन स्थानांतरण नीति लागू करके तबादला उद्योग को बंद कर अध्यापकों के सम्मान को बहाल किया गया। वहीं अध्यापकों से शुरू की गई यह व्यवस्था अब अन्य विभागों में भी लागू की जा चुकी है। 43 विभागों के 80 से अधिक पदों वाले 214 काडर में ऑनलाइन स्थानांतरण नीति लागू हो चुकी है।

प्रदेश के सभी गांवों को लाल डोरा मुक्त किया गया

गांवों में मालिकाना हक से संबंधित विवादों पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश में गांवों को लाल डोरा मुक्त करने की योजना 26 जनवरी, 2020 को शुरू की गई थी, जिसे बाद में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के नाम से पूरे देश में लागू किया गया। इस योजना के तहत प्रदेश के सभी गांवों को लाल डोरा मुक्त किया जा चुका है।

जगमग हो रहा हरियाणा

प्रदेश के गांवों में 24 घंटे बिजली मुहैया करवाई जा रही है। 'म्हारा गांव-जगमग गांव योजना' इस समय प्रदेश के 5,681 अर्थात 84 प्रतिशत गांवों को 24 घंटे बिजली दी जा रही है, जबकि अक्तूबर, 2014 में केवल मात्र 538 गांवों में 24 घंटे बिजली दी जा रही थी। अक्तूबर, 2014 में ग्रामीण क्षेत्र से बिजली बिलों की रिकवरी 50 प्रतिशत से भी कम थी, जो अब बढ़कर 90 प्रतिशत से अधिक हो गई है।

पढ़े-लिखे जन प्रतिनिधि

प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करके वर्ष 2015 में पंचायतों के प्रतिनिधियों के लिए शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित की गईं। इससे पंचायतों को स्वच्छ छवि के पढ़े-लिखे और पंच परमेश्वर की अवधारणा को सही मायने में चरितार्थ करने वाले जन-प्रतिनिधि मिले हैं। इस निर्णय की माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी सराहना की है।

स्पोर्टर्स हब के रूप में उभरा हरियाणा

हरियाणा पिछले कुछ वर्षों में स्पोर्ट्स हब के रूप में उभरा है। पदक विजेता खिलाड़ियों को सर्वाधिक नकद पुरस्कार देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। सरकार ने मेडल विजेता खिलाड़ियों की नौकरी सुनिश्चित की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मेडल जीतने वाले के लिए 550 पद वार्षिक आरक्षित किए गए हैं, जिसे आने वाले वक्त में बढ़ाएंगे।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकार की आठ मुख्य उपलब्धियों के अलावा अन्य उपलब्धियों का ज़िक्र करते हुए कहा कि वर्ष 2014 में राज्य में जन्म के समय लिंगानुपात 871 था, जो अब सुधरकर 923 हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी खजाने से नागरिकों को सहायता देने वाली सैकड़ों स्कीमों को डी.बी.टी. से जोड़ा और पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा करवाया जा रहा है। 150 योजनाएं डी.बी.टी. पोर्टल पर अपलोड कर दी गई हैं। इनमें से 94 राज्य योजनाएं और 56 केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं। वर्ष 2017 से अब तक कुल 29.63 करोड़ लेन-देन हुए हैं, जिनके तहत 52,374 करोड़ रुपए लाभार्थियों के खातों में डाले गये हैं। डी.बी.टी. कार्यान्वयन से गत 8 सालों में 36 लाख 75 हजार अपात्र लाभार्थी चिह्नित किये गये। इससे लगभग 6,700 करोड़ रुपए की बचत हुई है। राज्य को डी.बी.टी. मिशन, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान डी.बी.टी. के कार्यान्वयन में देश में प्रथम स्थान दिया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' के तहत पात्र सभी लगभग 10 लाख अंत्योदय परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक मुफ़्त इलाज के लिए गोल्डन कार्ड बनाए जा चुके हैं। राज्य में बीपीएल की आय सीमा 1 लाख 80 हजार रुपए वार्षिक से कम करके 1 लाख 20 हजार रुपए वार्षिक करने से 17 लाख अन्य परिवार इस योजना के पात्र बन गए हैं। इन सबके भी गोल्डन कार्ड बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 'वृद्धावस्था सम्मान भत्ता' अक्तूबर, 2014 में 1,000 रुपए मासिक था, जो अब बढ़कर 2,500 रुपए मासिक हो गया। वर्ष 2014 में वृद्धावस्था पेंशन भत्ता लाभार्थियों की संख्या 13 लाख थी, जो अब बढ़कर लगभग 18 लाख हो गई। जल्द ही पेंशन को 3,000 रुपए मासिक किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बिना भेदभाव के काम कर रही है। हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारे के तहत काम किया। सभी 22 जिलों में समान विकास कार्य हो रहे हैं। प्रदेश में मिशन मैरिट को प्राथमिकता दी गई। अब बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां मिल रही है। इसके अंदर समय-समय भ्रष्टाचार पकड़ा गया। कई तरह के नैक्सेस का भंडाफोड़ हुआ। कुल 771 लोग पकड़े गए और नौकरियां में भ्रष्टाचार को खत्म किया गया।

प्रदेश में पानी की उपलब्धता के लिए तीन बड़े डैम बनाए जा रहे हैं। 47 फीसदी पानी तीनों डैम से हरियाणा को मिलेगा। इसके साथ ही सरकार ने पानी को बचाने को कई कदम उठाए हैं। सरकार ने माइक्रो इरिगेशन का प्रोजेक्ट चलाया है। टेल तक पानी पहुंचाया तथा 14,000 तालाब ठीक किए जा रहे हैं। पहाड़ों पर चेकडैम भी बनाए जा रहे हैं। 'जल जीवन मिशन' के तहत प्रदेश में लगभग 18 लाख जल कनेक्शन देकर सभी गांवों के हर घर में नल से जल पहुंचाया जा चुका है।

प्रदेश में 5 राजकीय मेडिकल कॉलेज तथा फरीदाबाद, गुरुग्राम और पंचकूला के जिला अस्पतालों में हाई डिपेंडेंसी यूनिट और इंटेसिव केयर यूनिट की स्थापना के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।

हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत 43 विभागों व संस्थाओं की 622 सेवाएं अधिसूचित हैं , जो जीवन के विभिन्न चरणों में समाज के सभी वर्गों से ताल्लुक रखती हैं।

सतत विकास से सश

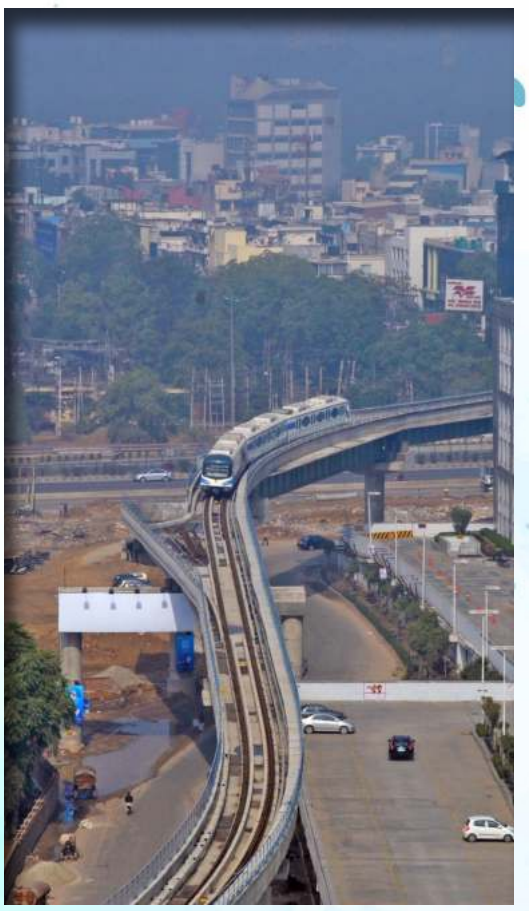

मनोज प्रभाकर

शिवालिक पर्वतमाला के गांव शाहपुर से अरावली क्षेत्र के गांव दोहा व जमुना किनारे के ताजेवाला से पंजाब से लगते गांव चौटाला तक के भू भाग को हरियाणा प्रदेश के तौर पर रेखांकित किया गया है। एक नवंबर 1966 को यह प्रदेश शासकीय व्यवस्था के तहत मानचित्र पर दर्शाया गया जिसके अनुसार प्रदेश 56 वर्ष का हो गया है।

हरियाणा की मूल संस्कृति की प्राचीनता का कोई तोड़ नहीं है। इसका इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मातृ भाषा हिंदी को हरियाणवी बोली की नानी कहा जाता है। खादर, बांगर, देशवाली व मध्य भाग में बंटे प्रदेश की संस्कृति लगभग एक है लेकिन बोली में फर्क आ जाता है। 'बीस कोस पै वाणी बदलै, डंग डंग पै पाणी।' वाली कहावत यहां सही चरितार्थ होती है।

विकास की बागडोर पहले संयुक्त पंजाब सरकार के हाथों में थी उसके बाद विकास से संबंधित तमाम निर्णय लेने की शक्ति अपनी हो गई। आरम्भ से लेकर आज तक कई सरकारें आई। हर सरकार के कार्यकाल में विकास कार्य हुए। किसी में ज्यादा तो किसी में कम। सबने अपनी-अपनी क्षमता के मुताबिक विकास कार्य कराए।

प्रदेश के बनने संवरने की यात्रा में अनेक चुनौतियां भी आई लेकिन स्थानीय लोगों ने उनका पूरे साहस के साथ मुकाबला किया और चरवैति-चरवैति की धुन से आगे बढ़ते चले गए। विकास कार्यों का इतिहास काफी लंबा चौड़ा है जिस पर चर्चा करना शायद उचित नहीं रहेगा। जिक्र वर्तमान करें तो बेहतर रहेगा कि आज हम कहां हैं और आगे कहां तक जा सकते हैं। क्या हम कमा चुके हैं और क्या अभी बाकि है। ध्यान इस पर भी देना होगा कि व्यवस्था में विसंगतियां कौन कौन सी हैं जिनको दूर किया जाना आवश्यक है।

उल्लेखनीय है कि राज्य की मनोहर सरकार इन सभी मोर्चों पर तत्परता से कार्य कर रही है। इन कार्यों का सौ फीसदी परिणाम तभी सामने आएगा जब सूबे के तमाम वर्ग, संगठन, संस्थाएं व आम लोग राष्ट्रीयता की भावना से अपने-अपने हिस्से का सहयोग देंगे।

कुल 44212 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले प्रदेश की जनसंख्या आज दो करोड़ 80 लाख के करीब है। जिलों की संख्या 22 है। 140 ब्लॉक हैं तो गांवों की संख्या 7356 है। साक्षरता दर 75 प्रतिशत के पार है। लिंगानुपात 920 पहुंच गया है।

लोगों की आजीविका का मुख्य साधन कृषि है। प्रदेश की जीडीपी विकास दर लगातार बेहतर हुई है। राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबर्द्धन गतिविधियों का 17 प्रतिशत, सर्विस सेक्टर का 47 प्रतिशत और उद्योग का 36 प्रतिशत योगदान है।

हरियाणा इकलौता ऐसा प्रदेश है जिसे धान का कटोरा कहा जाता है। यहां पर खेती मुनाफे की होती है। मिट्टी से लेकर मार्केट तक राज्य सरकार किसान के साथ है। फसल के वाजिब और पूरे दाम मिलते हैं। अगर किसी प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है तो उसकी भरपाई 'फसल बीमा योजना' व 'भावांतर भरपाई योजना' से होती है।

दृढ़संकल्प से हो रहा बदलाव

मनोहर सरकार ने जब से प्रदेश की बागडोर संभाली तब से सूबे की दशा और दिशा बदलती चली आ गई। मुख्यमंत्री ने प्रारंभ में ही संकल्प लिया था कि प्रदेश के लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए वह हर संभव प्रयास करेंगे, इसके लिए चाहे किसी भी चुनौती का सामना करना पड़े। उन्होंने पूरी ईमानदारी से कठोर परिश्रम किया। उन्होंने इस राह में विपक्ष की आलोचनाओं पर भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। सरकारी नौकरियों में काबिलियत के आधार पर नौकरी व विभागों में ऑनलाइन तबादलों ने तो सिस्टम में व्याप्त कथित मायाजाल का पासा ही पलट दिया।

प्रदेश के लोगों का जीवन सहज व सरल हो, मुख्यमंत्री ने इस पर विशेष ध्यान दिया। इसके लिए विभागों का कामकाज ऑनलाइन किया गया है ताकि लोगों को घर बैठे योजनाओं का लाभ मिल सके। उल्लेखनीय है कि डिज़िटलाइज होने से सरकारी दफ्तरों का माहौल बदल चुका है। तथाकथित दलाल गायब हैं। कार्य के प्रति कर्मचारियों व अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई हैं।

बदल गई चूल्हे चौके की तस्वीर

पंजाब प्रांत से अलग होने के बाद हरियाणा 56 वर्ष का हो गया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जितनी भी सरकारें बनीं, विकास कार्य हुए। विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसके होने से लोक जीवन में बदलाव अवश्यंभावी है। यह भी सच है कि लोगों को जब सुविधाएं मिलने लगती हैं तो सांस्कृतिक मूल्य पीछे छूटने लगते हैं। पिछले एक दशक पर नज़र डालें तो सूबे में बहुत कुछ बदला है और तेजी से बदला है। रसोई संस्कृति की बात करें तो बहुत कुछ बदल गया है।

प्रत्येक घर के चूल्हे चौके की तस्वीर बदल गई है। कुकिंग गैस से खाना बनता है। गांव की महिलाएं अब खेतों में ईंधन लेने नहीं जाती। वे सड़क किनारे कीकर या अन्य पेड़ों की डाल नहीं काटती। आरणे, मुढ़े व अन्य जलान की रिवाज़ तो कब की समाप्त हो चुकी है। महिलाएं अब धूएं में परेशान नहीं होती। गैस लाइटर का बटन दबाती हैं और भोजन पकाती हैं।

घरों में अब मिट्टी का तेल भी नहीं मिलता। उसके न होने से न तो स्टोव की आवाज़ सुनाई देती है और न मिट्टी के तेल के दीये जलते हैं। रसोई में चिमटा तो मिल जाएगा लेकिन फूंकनी गायब हो गई हैं। कई प्रकार की लकड़ी के धूएं से तवे पर जमने वाली स्याही से अब काजल नहीं बनाया जाता, जिसे अक्सर नवजात बच्चों की आंखों में लगाया जाता था। प्रसूति के उपरांत महिलाएं भी अपनी आंखों में इसी काजल का इस्तेमाल करती थीं।

वन या खेतों से लकड़ी लाने के लिए लगभग हर घर में कुल्हाड़ी या लोहे के दा होते थे। अब वे नहीं हैं। कुकिंग गैस आने से उनकी जरुरत नहीं रह गई है। बरानी खेतों को 'चलती जमीन' बना लिया गया है। उन तक पानी की पहुंच होने से उपजाऊ हो गए हैं।

जो परिवार पशु पालते हैं उनमें से आधे घरों में ही गोबर के उपले तैयार करते दिखाई देंगे जिनका उपयोग या तो पानी गर्म करने में होता है या उनसे बाखर तैयार किया जाता है। बहुत से पशुपालक अब उपले नहीं बनाते। वे गोबर का प्रयोग सीधे खेतों में करते हैं, कुछ गोबर गैस प्लांट में डाल देते हैं।

इन बदले हालात में अब कढ़ाई का वह दूध कहां और उस कढ़ाई के लाल दूध की लाल मलाई कहां दिखाई देती है। दूध या तो डेयरी में चला जाता है या उपभोक्ताओं द्वारा खरीद लिया जाता है।

बिलावणी तो हैं लेकिन उनका स्वरूप बदल गया है। मिट्टी की बिलावणी की जगह सिल्वर की डेगच दिखाई पड़ती हैं। बिलावणी में जो लकड़ी की बनी रई डलती थी उसकी जगह बिजली की आ गई है। लकड़ी की रई के चार फूलों से जब टिंडी घी उतारा जाता था तो उसकी खूशबू पूरे घर में फैल जाती थी। बाजरे की बासी रोटी पर टिंडी घी, अब कहां दिखाई पड़ता है। शाम की गोज़ी या उस बिलावणी का सीत अब जिक्रों में ही रह गया प्रतीत होता है।

गांवों में अब पर्याप्त बिजली मिल रही है। अधिकांश गांवों में तो 18 से 24 घंटे बिजली मिल रही है। बिजली के आने से भी रसोई की सूरत बदली है। लकड़ी व उपले जलाने से पहले की रसोई धूएं से काली होती थी। कभी दूध पकने, कभी बाजरे की खिचड़ी या अन्य पकवान बनने से उन रसोइयों से अजीब प्रकार की महक आती थी।

चूल्हे के आगे बैठकर खाना खाने की रिवाज़ थी। आंखों से पानी निकलता रहता था और खाना खाते रहते थे। पता ही नहीं चलता था कि मां द्वारा रोटी पर रखा गया टिंडी घी कब गले से उतर गया। सब्जी के नाम पर केवल हरी सब्जी या पानी वाली दाल होती थी। सच कहूं तो मन की बात चूल्हे पर ही होती थी। आज खेतों में तरह-तरह की सब्जियां उगाई जा रही हैं और उनका सेवन किया जा रहा है। रसोईघर एकदम साफ सुथरे हैं, जिनमें बहुत से लोगों ने तो पेयजल के लिए आरओ लगवाए हैं।

स्कूलों, कॉलेजों, पॉलिटेक्निकों में पढ़ने वाली बेटियां अब हरियाणा रोडवेज की पिंक बसों में सवारी करेंगी। इन बसों की खरीद भी जल्द पूरी होगी और इन्हें हरियाणा रोडवेज के बेड़े में शामिल किया जाएगा।

पानीपत व करनाल में एथनोल प्लांट लगाने का कार्य शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा शाहबाद में भी एथनोल प्लांट की क्षमता बढाई जाएगी। प्रदेश की सभी चीनी मिलों में एथनोल प्लांट लगाए जाने की योजना है।

क्त हरियाणा

केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई गई जनकल्याणकारी योजनाओं का फायदा प्रदेश के तमाम परिवारों को मिले इसके लिए राज्य सरकार अंतोदय की भावना से काम कर रही है। परिवार पहचान पत्र बनाए गए हैं। इनको 'आधार' से जोड़ा गया है ताकि कोई भी पात्र योजनाओं के लाभ से वंचित न रह जाए।

अमृत सरोवर योजना : ग्रामीण क्षेत्र के विकास की अति महत्त्वाकांक्षी योजना अमृत सरोवर योजना पर कार्य अपनी गति पर है। इस योजना के कार्यान्वित होने से पेयजल एवं सिंचाई जल की उपलब्धता में मदद मिलेगी। इनसे न केवल भूमिगत जल स्तर में सुधार होगा, गांवों का सौंदर्यीकरण भी होगा।

राज्य सरकार ने योजना के तहत अपने तय लक्ष्य से अधिक अमृत सरोवर बनाकर उपलिब्ध हासिल की है। 15 अगस्त, 2022 तक प्रदेश में 418 अमृत सरोवर बनाये जाने थे, लेकिन सरकार के अथक प्रयासों के फलस्वरूप 557 अमृत सरोवर बनाये जा चुके हैं। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाये जाने हैं। 4811 तालाबों का डिज़िटल सर्वे करवा लिया गया है और उसके बाद 3404 की शक्लोसूरत बनाने के लिए कार्य आवंटित कर दिया है।

लाल डोरा मुक्त से मिली राहत: आवंटन एवं बंटवारे के मकड़जाल में फंसी गांवों की जमीन को उक्त योजना से बड़ी राहत मिली है। चप्पा-चप्पा जमीन की निशानदेही हो गई है। अब लगभग स्पष्ट हो गया है कि किस जमीन का कौन मालिक है। ऐसा पहली बार हुआ है। कहा जा सकता है कि प्राचीन समय से चले आ रही जमीन के मालिकाना संबंधी दुविधा समाप्त हो गई है। राज्य के 44,212 वर्ग किमी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जीआईएस मानचित्र प्रणाली की परियोजनायें पूरे ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के लिए आरम्भ की गई।

1955 में उठी हरियाणा की मांग

संयुक्त पंजाब से हरियाणा को अलग राज्य बनाने की मांग पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरों के शासनकाल में प्रमुखता से उठी थी। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होने के समय हरियाणा पंजाब प्रांत का हिस्सा था। 1949 में पंजाब के मुख्यमंत्री भीमसेन सच्चर के शासनकाल में पंजाब प्रांत की भाषा को लेकर विरोध उत्पन्न हो गया। हिंदी भाषा क्षेत्रों में पंजाबी बढ़ाने का विरोध हुआ, परिणाम स्वरूप इसके समाधान के लिए सच्चर फार्मूला बनाया गया। पहली अक्तूबर 1949 को सच्चर फार्मूले को लागू कर दिया गया, इस फार्मूले के अनुसार पंजाब को पंजाबी क्षेत्र व हिंदी क्षेत्र में बांट दिया गया।

1955 में प्रदेश की सीमा निर्धारित करने रोहतक आए आयोग के समक्ष हरियाणा के विधायकों ने पृथक हरियाणा राज्य की मांग रखी। पंजाब के प्रताप सिंह कैरों के शासनकाल (1956-64) के दौरान ही पृथक हरियाणा की मांग ने ज़ोर पकड़ा। भारतीय संविधान में संशोधन (17 वा संशोधन 1956) होने के बाद राष्ट्रपति की आज्ञा से 24 जुलाई 1956 को पंजाब सरकार ने क्षेत्रीय फार्मूला राज्य में लागू कर दिया। प्रताप सिंह कैरों ने इसे पूरी तरह सफल होने के अवसर नहीं दिये। इससे क्षेत्रीय योजना असफल हो गई।

23 सितंबर 1965 को लोगों के दबाव में सरकार ने विभाजन के लिए सरदार हुकुम सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। कमेटी के फैसले को सही मानते हुए देश के गृहराज्य मंत्री ने संसद के दोनों सदनों में पंजाब के पुनर्गठन के संबंध में संसदीय समिति के गठन संबंधी निर्णय की घोषणा कर दी। हुकुम सिंह कमेटी की सिफारिशों को मानते हुए सरकार ने 23 अप्रैल 1966 को जे सी शाह की अध्यक्षता में सीमा आयोग का गठन किया। 18 सितम्बर, 1966 को पंजाब पुनर्गठन विधेयक पारित कर दिया गया तथा एक नवंबर 1966 को पृथक राज्य के रूप में हरियाणा देश के 17वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया।

खातों में आ रही पेंशन : वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना' के तहत 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्तियों, विधवा एवं बेसहारा महिलाओं, दिव्यांग, बौना व किन्नर की पेंशन 2,500 रुपए मासिक की गई है। लाडली पेंशन योजना के तहत 45 से 60 वर्ष की आयु तक के माता-पिता, जिनकी सन्तान एक या एक से अधिक केवल लड़कियां हों और वार्षिक आय 2 लाख से अधिक न हो, की पेंशन राशि भी 2,500 रु. मासिक की गई है।

पंचायती राज संस्थाएं

प्रदेश में अंतर जिला परिषद् का गठन किया है। इस परिषद् का गठन करके हमने ग्रास रूट के जन प्रतिनिधियों के लिए प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए मिल बैठकर व आपसी विचार-विमर्श से विकास की प्राथमिकताएं तय करने के लिए एक संस्थागत मंच उपलब्ध हुआ है।

पंचायतें गांवों की सरकार मानी जाती हैं। इसलिए प्रदेश में पढ़ी-लिखी पंचायतों का ऐतिहासिक फैसला लिया गया। अधिकार दिये गए। उन्हें शक्तियां प्रदान की गई हैं। पंचायतीराज संस्थाओं में और सुधार के लिए मतदाताओं को 'राइट टू रिकॉल' का अधिकार भी दिया गया है। सभी नगर निकायों को शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए कई कदम उठाए हैं। इस दिशा में, शहरी निकायों को मज़बूत करने के लिए मेयर का चुनाव सीधे करवाया जाता है।

रत्नावली महोत्सव

राज्यपाल एवं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि हरियाणा की संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के रत्नावली महोत्सव का अहम् योगदान रहा है। इस रत्नावली महोत्सव से युवाओं को प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत से आत्मसात करने का एक अवसर मिलता है और अच्छी शिक्षा और संस्कार भी मिलते हैं। दत्तात्रेय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के आडिटोरियम हॉल में युवा सांस्कृतिक एवं कार्यक्रम विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय रत्नावली महोत्सव में बोल रहे थे।

श्री दत्तात्रेय ने रत्नावली महोत्सव के शानदार आयोजन पर कुलपति प्रो. सोमनाथ सचदेवा और प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए कलाकारों को बधाई देते हुए कहा कि 8 विधाओं और 300 कलाकारों से शुरू होने वाले रत्नावली महोत्सव ने एक बड़ा स्वरूप ले लिया है। यह महोत्सव पूरे विश्व में पूरे हरियाणवी संस्कृति का परचम फहरा रहा है। इस महाकुंभ में अब 32 विधाओं में 3000 से ज्यादा कलाकार अपनी भागेदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। इस महोत्सव में युवा पीढ़ी के उत्साह को देखकर एक सुखद अहसास भी होता है कि आज युवा पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति से दूर हटकर हरियाणवी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं इस महोत्सव के माध्यम से युवा पीढ़ी हरियाणवी संस्कृति को सहेजने का काम भी कर रही है।

उन्होंने हरियाणवी लोककला प्रर्दशनी की प्रशंसा करते हुए कहा कि ग्रामीण आंचल में लोककला को प्रदर्शित करने वाली यह प्रर्दशनी युवा पीढ़ी को अहसास करवा रही है कि हरियाणवी संस्कृति दुनिया में सबसे अव्वल है और आज प्राचीन संस्कृति और संस्कारों को अपनाने की जरूरत है। यह महोत्सव नैतिक मूल्यों का भी अहसास युवा पीढ़ी को करवा रहा है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा ने आर्थिक विकास, कानुन व्यवस्था व सुशासन के मामले में नई छाप कायम की है। प्रदेश कृषि, शिक्षा, सुरक्षा, सेवा, स्वास्थ्य, सुशासन, खेल, आटो उत्पादन के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है। यह और भी विशेष बात है कि हमारे सभी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को पूरी तरह लागु करने के लिए तैयार हैं।

उन्होंने कहा कि आज हरियाणा प्रदेश की महिलाएं लोक संस्कृति, शिक्षा, खेल सहित अन्य सभी क्षेत्रों में बहुत आगे निकल चुकी हैं। इस प्रदेश की बेटियां हर क्षेत्र में एक मुकाम हासिल कर चुकी हैं।

विज्ञापन अनुमति तथा नगर निकायों के विज्ञापन स्थलों की ई-नीलामी के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। इससे निकायों में विज्ञापन अधिकारों के आवंटन में पारदर्शिता आएगी।

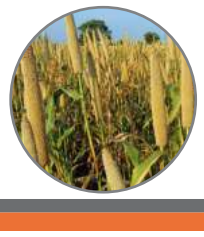

प्रदेश में इस बार बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,350 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि मंडियों में खरीद 1,850-1,900 रुपए प्रति क्विंटल हो रही है। इसके अलावा भावांतर योजना के तहत 450 रुपए का भुगतान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना

योजनाओं के तहत प्रीमियम व मुआवजा राशि निर्धारित

प्रतिकूल मौसम व प्राकृतिक आपदाओं के चलते बागवानी फसलों के नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना शुरु की है। इस योजना के तहत सब्जियों व मसालों के लिए 750 रुपए प्रति एकड़ प्रीमियम राशि निर्धारित की गई है, जबकि फलों के लिए प्रीमियम राशि प्रति एकड़ 1000 रुपए है। सब्जियों व मसालों के लिए न्यूनतम मुआवजा राशि 15 हजार रुपए प्रति एकड़ व अधिकतम 30 हजार रुपए है। इसी प्रकार फलों के लिए न्यूनतम मुआवजा राशि 20 हजार व अधिकतम 40 हजार रुपए है।

योजना में शामिल प्रतिकूल मौसम व प्राकृतिक आपदाएं :-

योजना के तहत ओलावृष्टि, तापमान, पाला, जलकारक, बाढ़, बादल फटना, नहर व ड्रेन का टूटना, जलभराव, आंधी, तूफान व आग।

योजना में शामिल की फसलें :-

योजना में 14 सब्जियों को शामिल किया गया है, जिनमें टमाटर, प्याज, आलू, फूल गोभी, मटर, गाजर, भिण्डी, घीया, करेला, बैंगन, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी व मूली शामिल है। इसी प्रकार पांच फलों को भी योजना में शामिल किया गया है। इनमें आम, किन्नू, बेर, अमरूद व लीची शामिल है। योजना में दो मसाले शामिल किए गए हैं, जिनमें हल्दी व लहसुन शामिल है।

योजना में देय बीमा राशि व प्रीमियम :-

फसल, सब्जियां व मसाले के लिए बीमा राशि 30 हजार रुपए प्रति एकड़ है, जबकि इसके लिए प्रीमियम राशि (2.5 प्रतिशत) 750 रुपए प्रति एकड़ है। फसल फल के लिए बीमा राशि 40 हजार रुपये प्रति एकड़ निर्धारित की गई है, जबकि प्रीमियम राशि (2.5 प्रतिशत) 1000 रुपये प्रति एकड़ है।

योजना में प्रति एकड़ मुआवजा राशि

नुकसान प्रतिशत आंकलन के लिए चार श्रेणी बनाई गई है। 0 से 25 प्रतिशत, 26 से 50 प्रतिशत, 51 से 75 प्रतिशत व 75 से 100 प्रतिशत है। बागवानी विभाग की टीम द्वारा मौके पर जाकर नुकसान का आंकलन किया जाएगा। नुकसान प्रतिशत के अनुसार ही मुआवजा दर को भी चार श्रेणी में बांटा गया है। सब्जियों एवं मसालों के लिए यदि नुकसान 0 से 25 प्रतिशत है तो मुआवजा शून्य रहेगा। इसके बाद निरंतर 26 से 50 प्रतिशत नुकसान के लिए 15 हजार रुपये प्रति एकड़ तथा फलों के लिए 20 हजार रुपये प्रति एकड़ दिया जाएगा। यदि नुकसान 51 से 75 प्रतिशत है तो सब्जियों व मसालों के लिए 22500 रुपये प्रति एकड़ तथा फलों के लिए 30 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा। इसी प्रकार यदि किसान की फसल में नुकसान दर 76 से 100 प्रतिशत होता है तो मुआवजा सब्जियों व मसालों के लिए 30 हजार रुपये प्रति एकड़ व फलों के लिए 40 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाएगा।

मुआवजा राशि सीधे पंजीकृत किसानों के खाते में स्थानांतरित होगी और राशि समिति द्वारा सर्वेक्षण पर आधारित होगी।

कैसे ले योजना का लाभ :-

मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का पोर्टल 15 सितंबर से खुल चुका है। इस योजना का लाभ लेने के लिए सर्वप्रथम किसानों को अपनी बागवानी की फसलों का पंजीकरण बागवानी पोर्टल पर करवाना अनिवार्य है, जिसका लिंक www.khushal-bagwani.hortharyana.gov.in खुशहाल बागवानी पोर्टल में जाकर मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना www.mbby.hortharyana.gov.in लिंक को खोलना होगा, वहां पर किसान अपना पंजीकरण करें और मौसम के अनुसार बागवानी फसलों का चयन करके अपना क्षेत्र भर कर अपनी प्रीमियम राशि देय कर दें। इसके बाद जो पेज आए उसका प्रिंट निकाल कर अपने पास रख ले।

मधुमक्खी पालन से युवाओं को मिला रोज़गार

संगीता शर्मा

किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में मधुमक्खी पालन एक बेहतरीन विकल्प है। अब युवाओं ने इसे व्यवसाय के रूप में अपनाना शुरू कर दिया है। यह व्यवसाय कम लागत के साथ शुरू किया जा सकता है। यह कृषि व बागवानी उत्पादन बढ़ाने की क्षमता भी रखता है। इससे शहद एवं मोम के अतिरिक्त अन्य पदार्थ, जैसे गोंद (प्रोपोलिस, रायल जैली, डंक-विष) भी प्राप्त होते हैं। इसका प्रयोग करके मधुपालक अनेक उत्पाद बनाते हैं और उनकी मार्केटिंग करते हैं। हरियाणा सरकार ने भी मधुपालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए और शहद उत्पादन को बढ़ाने की दृष्टि से 'मधुमक्खी पालन नीति-2021' बनाई गई है। मधुमक्खी पालन की पहल को अपनाने के लिए 5,000 नए किसानों को प्रेरित करने का लक्ष्य दिया गया है और इसके लिए राज्य सरकार किसानों को सहायता प्रदान कर रही है। इस नीति से अंतर्गत हरियाणा सरकार एकीकृत मुधमक्खी पालन विकास केंद्र (आईबीडीसी), रामनगर, कुरुक्षेत्र को मज़बूत किया जा रहा है और इसे राष्ट्रीय महत्त्व के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। राज्य में सभी मधुमक्खी पालन विकास योजनाओं को एकल एजेंसी/विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

मधुमक्खी पालन बना रोजगार

आज कल मधुमक्खी पालन ने कम लगत वाला कुटीर उद्योग का दर्ज़ा ले लिया है। ग्रामीण भूमिहीन बेरोज़गार किसानों के लिए आमदनी का एक साधन बन गया है। हरियाणा में शहद उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार मधुमक्खी पालन पर जोर दे रही है। कोरोना लॉकडाउन के बाद मनोहर लाल सरकार ने शहद उत्पादन में भी सिरमौर बनने का निर्णय लिया है। इसके लिए विभिन्न मदों में अनुदान राशि 40 फीसदी से बढ़ाकर 85 फीसदी तक कर दी गई है। सरकार का इसके पीछे मुख्य उद्देश्य किसानों को मधुमक्खी पालन की तरफ आकर्षित करना है।

अधुसंधान और विकास के लिए धन उपलब्ध

मधुमक्खी पालन नीति के तहत पोषण सुरक्षा के लिए सरकार शिक्षा, खेल विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिये जा रहे मध्याह्न भोजन और खिलाड़ियों और महिलाओं के आहार में मधुमक्खी पराग और शहद को शामिल करेगी। सरकार राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को मधुमक्खी पालन के विभिन्न घटकों जैसे एकीकृत कीट प्रबंधन, रॉयल जेली, मधुमक्खी विष, विभिन्न फसल प्रजातियों में अमृत और पराग की उपलब्धता और हरियाणा के पुष्प कैलेंडर पर अधुसंधान और विकास के लिए धन उपलब्ध कराएगी।

अनुकूल पौधों की प्रजातियों को बढ़ावा

सरकार मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में मधुमक्खी पालन की विभिन्न परियोजनाओं को वित्तपोषित करेगी। सरकार वन भूमि, सड़क किनारे, रेलवे भूमि और बंजर भूमि में मधुमक्खी के अनुकूल पौधों की प्रजातियों को बढ़ावा देगी, ताकि शहद उत्पादन में इज़ाफा हो सकें। सरकार मधुमक्खी पालन के औजारों/उपकरणों पर कर प्रोत्साहन देंगी। इसके अंतर्गत सरकार निरीक्षण और निगरानी द्वारा निषिद्ध कीटनाशकों की बिक्री को नियंत्रित करेगी और ग्रीन लेबल कीटनाशकों के उपयोग को बढ़ावा देगी।

शहद उत्पादन 2030 तक होगा दोगुना

हरियाणा सरकार मधुमक्खी बॉक्स व कालोनी पर 85 प्रतिशत अनुदान व मधुमक्खी उपकरणों पर 75 प्रतिशत अनुदान दे रही है। हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में मधुमक्खी पालन नीति भी बनाई गई है, जिसमें मधुमक्खी बॉक्स व शहद उत्पादन को 2030 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। हमारा हर संभव प्रयत्न रहेगा कि हम आगामी वर्षों में मधुमक्खी पालन को नई ऊंचाईयों पर लेकर जा सके। आईबीडीसी, रामनगर, कुरुक्षेत्र भारत का सबसे अच्छा केंद्र है जो मधुमक्खी पालन से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध करवाता है।

- जे.पी. दलाल, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, हरियाणा

तकनीकी हस्तक्षेप

वर्ष 2030 तक मधुमक्खी पालकों और मधुमक्खी कॉलोनियों की संख्या को दोगुना कर दिया जाएगा। मधुमक्खी कॉलोनियों का पता लगाने एवं निगरानी जीपीएस सिस्टम के माध्यम से व शहद और अन्य उत्पादों के लिए ई-मार्केट प्लेस, डिजिटल मार्केटिंग ई-शिक्षा शुरू की जाएगी। शहद की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार मधुमक्खी पालकों को खाद्य ग्रेड बाल्टी, खाद्य ग्रेड स्टेनलेस उपकरण और बेहतर रानी मधुमक्खियों पर सब्सिडी प्रदान करेगी। सरकार मधुमक्खी के छत्ते के उप-उत्पादों जैसे मधुमक्खी के मोम, पराग, प्रोपोलिस, रॉय जैली और मधुमक्खी के जहर के उत्पादन और संग्रह को बढ़ावा देगी जिससे मधुमक्खी पालकों को राजस्व सृजन में मदद मिलेगी।

मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण

राज्य में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा इस केंद्र के माध्यम से पिछले तीन वर्षों में हरियाणा के लगभग 400 किसानों को 25,000 कैल की लकड़ी से निर्मित सुपर बॉक्स दिए जा चुके हैं। इस केंद्र से पिछले चार वर्षों में लगभग 4,800 मधुमक्खी पालक/किसान भिन्न-भिन्न प्रकार की सुविधाओं का लाभ ले चुके हैं। इस केंद्र पर शहद की मंडी भी बनाई जा रही है ताकि मधुमक्खी पालकों को शहद की गुणवत्ता के आधार पर उचित दाम मिल सके तथा शहद के खरीददारों एवं निर्यातकों को उच्च गुणवत्ता का शहद एक ही स्थान से मिल सके। डॉ. बिल्लू यादव, उप-निदेशक उद्यान एवं केंद्र संचालक ने बताया कि अधिक से अधिक लोगों को मधुमक्खी पालन से जोड़ने के लिए उन्हें वैज्ञानिक विधि द्वारा मधुमक्खी पालन पर प्रशिक्षण दिया जाता है। सभी हरियाणा के निवासी कौशल पोर्टल पर आवेदन करके निशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। प्रशिक्षण के लिए किसान kaushal.hortharyana.gov.in पर पंजीकरण करवा सकते हैं।

वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात से कनेक्टिविटी बढ़ने से हरियाणा के लोगों को ख़ासा फ़ायदा होगा। यह ट्रेन हिमाचल के ऊना से चलेगी और चंडीगढ़ होते हुए दिल्ली पहुंचेगी। ट्रेन का ठहराव अंबाला में भी होगा।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने 'पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि' के लिए बिजली निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किये गए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित रूप में सुलझाया जा सके।

नानक तेरा-तेरा

नानक ने एक अनूठे धर्म को जन्म दिया, जिसमें गृहस्थ और संन्यासी एक ही हैं। और वही आदमी अपने को सिक्ख कहने का हकदार है, जो गृहस्थ होते हुए संन्यासी हो, और संन्यासी होते हुए गृहस्थ हो।

सिक्ख होना बड़ा कठिन है क्योंकि सिक्ख का अर्थ है- संन्यासी, गृहस्थ एक साथ। रहना घर में और ऐसे रहना जैसे नहीं हो। रहना घर में और ऐसे रहना जैसे हिमालय में हो। करना दुकान, लेकिन याद परमात्मा की रखना। गिनना रुपए, नाम उसका लेना।

नानक को जो पहली झलक मिली परमात्मा की, जिसको सतोरी कहें, वह मिली एक दुकान पर, जहां वे तराजू से गेहूं और अनाज तौल कर किसी को दे रहे थे। तराजू में भरते और डालते। कहते-एक, दो, तीन...दस, ग्यारह, बारह... फिर पहुंचे वे 'तेरा'। पंजाबी में तेरह का जो रूप है, वह 'तेरा'। उन्हें याद आ गई परमात्मा की। 'तेरा', दाईन, दाऊ-धुन बन गई। फिर वे तौलते गए, लेकिन संख्या तेरा से आगे न बढ़ी। भरते, तराजू में डालते और कहते 'तेरा'। भरते, तराजू में डालते और कहते तेरा। क्योंकि आखिरी पड़ाव आ गया। तेरा से आगे कोई संख्या है? मंज़िल आ गई। 'तेरा' पर सब समाप्त हो गया।

लोगों को लगा कि नानक सामान्य दुनियादार नहीं। लोगों ने रोकना भी चाहा, लेकिन वे तो किसी और ही लोक में हैं। वे तो कहे जाते हैं 'तेरा'। डाले जाते हैं, तराजू से तौले जाते हैं, और तेरा से आगे ही नहीं बढ़ते। तेरा से आगे बढ़ने की जगह ही कहां है। दो ही तो पड़ाव हैं, या तो 'मैं' या 'तू'। मैं से शुरुआत है, तू पर समाप्ति है।

नानक संसार के विरोध में नहीं हैं। नानक संसार के प्रेम में हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि संसार और उसका बनाने वाला दो नहीं। तुम इसे भी प्रेम करो, तुम इसी में उसको प्रेम करो। तुम इसी में उसको खोजो।

नानक जब युवा हुए, तब घर के लोगों ने कहा, शादी कर लो। उन्होंने 'नहीं' न कहा। सोचते तो रहे होंगे घर के लोग कि यह नहीं कहेगा। बचपन से ही इसके ढंग अलग थे। नानक के पिता तो परेशान ही रहे। उनको कभी समझ में न आया कि मामला क्या है। भजन में, कीर्तन में, साधु-संगत में...।

भेजा था बेटे को सामान खरीदने दूसरे गांव। बीस रुपए दिए थे। सामान तो खरीदा, लेकिन रास्ते में साधु मिल गए, वे भूखे थे। पिता ने चलते वक्त कहा था, सस्ती चीज़ खरीद लाना और इस गांव में आकर महंगी बेच देना। यही धंधे का गुर है। दूसरे गांव में सस्ते में खरीदना, यहां आकर महंगे में बेच देना। यहां जो चीज़ सस्ती हो खरीदना, दूसरे गांव में महंगे में बेचना। वही लाभ का रास्ता है। तो कोई ऐसी चीज़ खरीदकर लाना, जिसमें लाभ हो। नानक लौटते थे खरीदकर, मिल गई साधुओं की एक जमात। पांच दिन से भूखे थे वे साधु । नानक ने पूछा, भूखे बैठे हो। उठो, कुछ करो। जाते क्यों नहीं गांव में? उन्होंने कहा, यही हमारा व्रत है। जब उसकी मर्ज़ी होगी वह देगा। तो हम आनंदित हैं। भूख से कोई अंतर नहीं पड़ता।

तो नानक ने सोचा कि इससे ज्यादा लाभ की बात क्या होगी कि इन साधुओं को यह भोजन बांट दिया जाए जो मैं खरीद लाया हूं दूसरे गांव से? पिता ने यही तो कहा था कि कुछ काम लाभ का करो।

उन्होंने वह सब सामान साधुओं में बांट दिया। साथी था साथ में, उसका नाम बाला था। उसने कहा क्या करते हो, दिमाग़ ख़राब हुआ है। नानक ने कहा, यही तो कहा था पिता ने कुछ लाभ का काम करना। इससे ज्यादा लाभ क्या होगा? बांट कर वे बड़े प्रसन्न घर लौटे।पिता ने कहा भी कि ऐसे तो व्यापार चौपट हो जाएगा। और नानक ने कहा, 'आप नहीं सोचते कि इससे ज्यादा लाभ की और क्या बात होगी? लाभ कमा कर लौटा हूं।'

लेकिन यह लाभ किसी को दिखाई नहीं पड़ता था। नानक के पिता कालू मेहता को तो बिलकुल दिखाई नहीं पड़ता था। उनको तो लगता था, लड़का साधु संगत में बिगड़ गया। होश में नहीं है। सोचा कि शायद स्त्री से बांध देने से राहत मिल जाएगी।

अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं। सोचने का कारण है क्योंकि संन्यासी स्त्री को छोड़कर भागते हैं तो अगर किसी को गृहस्थ बनाना हो, तो स्त्री से बांध दो। पर नानक पर यह तरकीब काम न आई क्योंकि यह आदमी किसी चीज़ के विरोध में न था। पिता ने कहा, 'शादी कर लो।'

नानक ने कहा, 'अच्छा'। शादी हो गई, लेकिन उनके ढंग में कोई फर्क नहीं पड़ा। बच्चे हो गए, लेकिन उनके ढंग में कोई फर्क न पड़ा। इस आदमी को बिगाड़ने का उपाय ही न था, क्योंकि संसार और परमात्मा में उन्हें कोई भेद न था।

तुम बिगाड़ोगे कैसे? जो आदमी धन छोड़कर संन्यासी हो गया, उसे बिगाड़ सकते हो- धन दे दो। जो आदमी स्त्री छोड़कर संन्यासी हो गया, एक सुंदर स्त्री उसके पास पहुंचा दो, बिगाड़ सकते हो। लेकिन जो कुछ छोड़कर ही नहीं गया, उसको तुम कैसे बिगाड़ोगे? उसके पतन का कोई रास्ता नहीं है। जिसने मान लिया कि सब 'तेरा ही तेरा' है , उसे किसी मेरे में फंसाया नहीं जा सकता।

- आचार्य रजनीश

हरियाणा का कथा साहित्य

हरियाणा का अधिकतर साहित्य लोक संस्कृति पर आधारित है। अधिकांश लोक साहित्य भाटों, चारणों द्वारा गाथाओं के रूप में सुनाया जाता रहा। शौर्य गाथाएँ वाद्य यंत्रों के बिना भी गाई जाती रही हैं। इनमें सूफी कवि मलिक मुहम्मद जायसी लिखित पद्मावत्, हीर-रांझा की प्रेमकथा, शकुंतला, राजा भोज आदि व आल्हा-ऊदल, पृथ्वीराज रासो भी सम्मिलित हैं। हिन्दी साहित्य-की लम्बी परम्परा में हिन्दी कहानी की यात्रा अब तक सौ वर्षों से ऊपर की यात्रा रही है।

1 नवम्बर 1966 के इन चार दशकों की समस्याओं को हरियाणा के कहानीकारों व उपन्यासकारों ने अपनी जिस पैनी दृष्टि से देखा व महसूस किया उनमें प्रमुख कथाकारों के नाम हैं- राकेश वत्स, स्वदेश दीपक, पृथ्वीराज मोंगा, यशपाल वैद, उर्मि कृष्ण, विकेश निझावन, ज्ञान प्रकाश विवेक, ललित कार्तिकेय, दिबेन, सत्यपाल सक्सेना, रोहिणी अग्रवाल, कमला चमोला, भगवानदास मोरवाल, अमृतलाल मदान, पूरन मुद्गल, चंद्रकान्ता, डॉ .पुष्पा बंसल, बैजनाथ सिंहल, राजेन्द्र वत्स, पुष्पा मानकोटिया, सुधा जैन, तारा पंचाल, रामकुमार आत्रेय, कृष्णा बाछल, मधुकांत, श्याम सखा 'श्याम', पुष्पराज चसवाल, सुभाष रस्तोगी, रूप देवगुण, मनमोहन गुप्ता मोनी, श्रीनिवास वत्स, राजेन्द्र मोहन भटनागर, प्रीति श्रीवास्तव तथा डॉ प्रेमलता चसवाल %प्रेमपुष्प%आदि।

बेहद चर्चित कथाकार व उपन्यासकार स्वदेश दीपक ने साहित्य जगत में अपनी रचनाओं के कारण एक गहरी पैठ बनाई। नाटक 'कोर्टमार्शल' से तो इन्हें प्रसिद्धी मिली ही, कहानी व उपन्यास में भी उतनी ही शौहरत हासिल की।

राकेश वत्स हरियाणा के चर्चित कथाकार रहे हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई। इन्होंने दस उपन्यास, आठ कहानी संग्रह, चार संपादित पुस्तकें एवं कविता तथा आलोचना पर भी पुस्तकें दीं। इनके कुछ चर्चित कहानी संग्रह अन्तिम प्रजापति, पहर एक रोज़ का, इन हालात में अतिरिक्त तथा अन्य कहानियाँ, महाकवि के वारिस व मेरी खास कहानियाँ प्रमुख हैं। इनके उपन्यास जंगल के आसपास, सपन राग, नरदंश तथा फिर लौटते हुए खूब चर्चित रहे। राकेश वत्स ने दस वर्ष तक 'मंच' जैसी साहित्यिक पत्रिका का संपादन, संचालन किया तथा 'सि य कहानी' आंदोलन भी शरू किया।

वरिष्ठ कथाकार कृष्णा बाछल का हाल ही में प्रकाशित उपन्यास 'अजन्मी चीख' में बीसवीं सदी के हरियाणा का लोक-जीवन तो है ही, तत्कालीन रीति-रिवाज़, रिश्तों की परस्पर निर्भरता, जातीय समीकरण और राष्ट्रीय आंदोलनों की झलक मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता है 'नारी सशक्तीकरण और भ्रूण-रक्षा' के लिये उनकी प्रतिबद्धता। शादी, रिश्तों, चारदीवारी व अनपढ़ता की बेड़ियों को पायदान बनाकर क्षितिज की ओर बढ़ते औरत के कदम और कोख पर हाथ रखकर सुरक्षित होने और सुरक्षित रखने का प्रयास युगीन मानवता को आश्वासन देता प्रतीत होता है।

हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र की जातियों, उनके रीति-रिवाज, रिश्तों में परस्पर निर्भरता और सम्बन्ध सेतुज जीवन के सभी पक्षों को लेखिका ने इस उपन्यास में बहुत जीवन्तता से प्रस्तुत किया है।

अपनी बहुमुखी प्रतिभा के साथ अमृतलाल मदान ने भी कहानी व उपन्यास में अच्छी पैठ पायी है। नाटक और कविता के अतिरिक्त कहानी व उपन्यास को भी अपनी संवेदना के बल पर अच्छी पहचान दी। उपन्यास 'लाल धूप, अपने अपने अँधेरे, सिन्धु पुत्र, विराट बौना, बंद होते दरवाजे, एक अधूरी प्रेमकथा, दूसरा अरुण 'बाल उपन्यास', एक समानान्तर प्रेमकथा, %हे पिता! .. संस्मरणात्मक उपन्यास,' अनंत प्रेमकथा, अमर प्रेमकथा, इति प्रेमकथा तथा वे अठारह दिन। इन सब उपन्यासों में 'लाल धूप' अत्यधिक चर्चित रहा।

पृथ्वीराज मोंगा कहानी व उपन्यास विधा को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में सफल रहे। धर्मयुग, सारिका, कहानी जैसी पत्रिका में इनकी कहानियाँ छपती रहीं और सातवें आठवें दशक में इनका लेखन उत्कर्ष पर रहा। इनके कहानी संग्रह 'वह कोई एक', 'उसकी पहचान' तथा उपन्यास 'सूना घोंसला' और 'काँच का आदमी' प्रमुख थे।

हरियाणा के कथाकारों में ज्ञानप्रकाश विवेक ने साहित्य की लगभग हर विधा को बड़ी खूबसूरती से पेश किया। पिताजी चुप रहते हैं, जोसफ़ चला गया जैसी कहानियां भीतर तक स्पन्दित करती हैं । इनके कहानी संग्रह अलग-अलग दिशाएँ, जोसफ़ चला गया, शहर गवाह है, उसकी ज़मीन, इक्कीस कहानियाँ, शिकारगाह, सेवानगर कहाँ है, मुसाफ़िरखाना कहाँ है तथा %बदली हुई दुनिया% प्रकाशित हुए। इनके उपन्यास गली नम्बर तेरह, आखेट, चाय का दूसरा कप तथा तलघर भी प्रकाश में आये। ज्ञान प्रकाश विवेक की कहानी 'पण्डित जी' मानव मन की बहुत ही संवेदनशील तथा स्वाभाविक प्रवृत्ति की कहानी उनको अलग ही पहचान देती है।

पुष्पराज चसवाल ने उपन्यास तथा कविता में अपनी पहचान बनाई है। 'कर्मक्षेत्र' उपन्यास विशेषरूप से चर्चित रहा। किस प्रकार औद्योगिक संस्थानों, सेवा-क्षेत्रों व सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों तथा अधिकारियों में परस्पर सद्भाव-सहकार का सौहार्दपूर्ण रचनात्मक वातावरण सम्पुष्ट हो, जिससे 'श्रम की गरिमा' के सिद्धांत का सम्मान सुनिश्चित किया जा सके। जनसामान्य, विशेषतः युवापीढ़ी के लिये यह उपन्यास दिशा देने वाला तथा पठनीय है। सत्तर के दशक में हरियाणा हिन्दी साहित्य सम्मेलन गुड़गांव में पुष्पराज जी की विशेष भूमिका रही।

तारा पांचाल, सरबजीत, रघुबीर सिंह मथाना,नवरत्न पांडे, ललित कार्तिकय ने अपनी अभिनव शैली और विभिन्न सूत्रों से जुड़े कथानक के बल पर अपनी अलग पहचान बनाई। रामकुमार आत्रेय हरियाणा के वरिष्ठ रचनाकार बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी हैं। कहानी, कविता, लघुकथा व बाल रचनाओं पर भी कलम चलायी। हिन्दी की विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में इनकी रचनाएँ छपती रहीं। आकाशवाणी व दूरदर्शन के अनेक कार्य' में में इनकी भागीदारी बनी रही। इनके अनेक कविता संग्रह व लघुकथा संग्रह प्रकाशित हुए। इनका कहानी संग्रह 'पिलूरे तथा अन्य कहानियाँ' विशेष रूप से चर्चित रहा। 'पिलूरे' कहानी प्रतीकात्मक है। ढाबों पर अवैध धंधा करने वाली स्त्रियों की कहानी है यह। ढाबे वाले उन स्त्रियों को अपनी भाषा में पिलूरे' कहते हैं।

महिला कथाकारों में चन्द्रकान्ता, उर्मि कृष्ण, रोहिणी अग्रवाल, कमल कपूर, कमला चमोला, प्रेमपुष्प तथा अंजु दुआ जैमिनी ने कथा-साहित्य में उल्लेखनीय कार्य किया है।

हरियाणा के कथाकारों की सूचि पर दृष्टि डालें तो यह बात स्वतः स्पष्ट हो जाती है कि प्रदेश में कथा साहित्य अपनी पूरी गति के साथ आगे बढ़ रहा है और भविष्य के लिये हम इसके प्रति पूरी तरह से आशान्वित हैं।

विकेश निझावन

'ग्राम संरक्षक योजना' के तहत आवंटित कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में एक अलग से प्रकोष्ठ बनाया जाएगा ताकि गांव की फीडबैक ली जा सके और मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा विश्लेषण किया जा सके ।

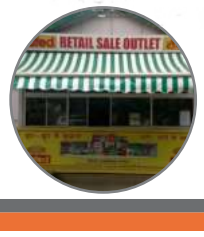

हैफेड ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 207 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड मुनाफ़ा कमाया है जो 55 सालों में सबसे अधिक है। इस अवधि के दौरान हैफेड ने सबसे अधिक टर्नओवर लगभग 17,700 करोड़ रुपए प्राप्त कर लिया है।

आस्था की डुबकी

कुरुक्षेत्र के पवित्र ब्रह्मसरोवर में आयोजित सूर्य ग्रहण मेले पर लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। यहां लोगों की सहूलियत के लिए बेहतर इंतज़ाम किए गए थे। बता दें कि इस ऐतिहासिक सूर्य ग्रहण के चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहले से जिला प्रशासन को पूरे इंतजाम करने के निर्देश दिए थे। उन्हीं के दिशा-निर्देश पर जिला प्रशासन ने ट्रैफिक, सुरक्षा व्यवस्था, बसों, रेलगाड़ियों व अन्य यातायात के साधनों की व्यवस्था की थी।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस तरह के आयोजनों को सफलतापूर्वक पूरा करना चुनौतीपूर्ण कार्य होता है लेकिन हरियाणा सरकार ने इसे बेहतर तरीके से पूरा किया है। उन्होंने कहा कि लाखों लोग कुरुक्षेत्र पहुंचे जबकि इतने ही लोगों ने कुरुक्षेत्र प्रशासन की कुरुक्षेत्र दर्शन मोबाइल ऐप पर इस घटना को देखा। इस मोबाइल ऐप पर सूर्यग्रहण मेले से संबंधित तमाम अहम जानकारियां अपलोड की गई थी।

अलग-अलग स्नान की व्यवस्था

संतों से लेकर अन्य श्रद्धालुओं के लिए स्नान की अलग-अलग व्यवस्था की गई थी। युद्धिष्ठर घाट पर शाही स्नान की व्यवस्था की गई थी। घाटों पर बिजली, पीने के पानी, शौचालयों की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ अन्य प्रकार के इंतजाम कर दिए गए थे। मेला क्षेत्र को 20 सेक्टरों में बांटा गया था और 4,500 पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। मेले को लेकर छोटे से छोटे पहलू को जहन में रखकर तैयारी की गई थी। इसके साथ-साथ 400 बसों व स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई थी। मेला स्थल के आसपास 370 सीसीटीवी, 25 जगह पार्किंग की व्यवस्था और 260 ई-रिक्शा को मुफ़्त चलाया गया था।

आस्था और पर्यटन का संगम है कुरुक्षेत्र

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गीता स्थली कुरुक्षेत्र आस्था और पर्यटन का संगम है। पिछले दिनों पवित्र तीर्थ ज्योतिसर में भगवान श्रीकृष्ण के विराट स्वरूप की मूर्ति का अनावरण किया गया था। अब जल्द ही यहां पर थ्री-डी प्रोजेक्शन मैपिंग शो भी देखने को मिलेगा। इसका लगभग कार्य पूरा हो चुका है। आने वाले दिनों में इस शो का उद्घाटन किया जाएगा। महाभारत और श्रीमद्भागवत गीता से जुड़े प्रसंगों को दिखाया जाएगा। इसके लिए अत्याधुनिक तकनीक जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी, होलोग्राफिक इमेज, रोबोटिक और ड्रोन आदि का इस्तेमाल किया जाएगा। ज्योतिसर तीर्थ पर पहले भी 2019 से एक लाइट एंड साउंड शो चल रहा है। इसके अतिरिक्त सरकार ने ज्योतिसर तीर्थ का परिक्रमा पथ भी बनवाया है। तीर्थ पर लाइटिंग का कार्य किया गया है और प्राचीन वट वृक्ष की सुरक्षा के लिए दीवार भी तैयार करवाई गई है। कुरुक्षेत्र अध्यात्मिक का केंद्र है, सरकार इसके विकास पर तत्परता से कार्य कर रही है।

श्री कृष्ण उत्सव मनाया जाएगा

धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र की नगरी का विकास करने के लिए कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड द्वारा 48 कोस सर्किट के तहत 164 स्थानों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इन स्थानों पर स्थित मंदिरों और सरोवरों को विकसित किया जा रहा है। जिस प्रकार अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का भव्य तरीके से आयोजन किया जाता है उसी प्रकार आने वाले समय में श्री कृष्ण उत्सव भी मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृष्णा सर्किट योजना के तहत हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार द्वारा कुरुक्षेत्र को ऐसा तीर्थ स्थल बनाया जा रहा है, जो आकर्षण का केंद्र बनेगा। कुरुक्षेत्र में तिरुपति बालाजी का एक मंदिर बन रहा है। इस्कॉन मंदिर, अक्षरधाम मंदिर बन चुके हैं। गीता ज्ञान संस्थानम भी गीता के ज्ञान के प्रसार के लिए बहुत बड़ा संस्थान बनने वाला है। यहां रिसर्च का काम भी चल रहा है।

सुण छबीले बोल रसीले

गांव का सियासी दंगल

-छबीले, आज्या आज्या, उरेन। आज कित ज्योड़ा तुड़ाए जा सै?

- भाई रसीले, कालू टेलर मास्टर कै जा सूं। दो जोड़ी कुड़ते पायजामें सिमवाण।

- सरपंची का फार्म तो भर दिया ईब वोट मांगण खातिर गाम में हांडणा भी तो पड़ैगा।

- झकोई फार्म तो तनै घर आली का भरवाया सै। कुड़ता पायजामा आपणा सिमवाण जा सै?

- अरै बावली बूच, वोट मांगण खातिर तो मनै भी घर-घर जाणा पड़ैगा।

- भाभी के भी दो-चार सूट सिमवाए सैं अक नहीं?

- उसके भी सिमवा दिए।

- छबीले तूं तो आपणे टाल मारै। तनै भी के जरुरत थी।

- वो क्यूं भाई?

- लैक्शन में उक-चूक लागगी तो वे कुड़ते पायजामे के काम आवैंगे?

- इसा माड़ा क्यूं बोलै सै बैरी, लैक्शन लड़ैंगे और जीतण खातिर लड़ैंगे।

- मैं तो ज्याएं तैं कहूं सूं छबीले, अक तूं और भाभी दोनूं शरीफ माणस हो। और गाम-राम शरीफ माणसां नै गाम की चौधर कम ऐ दिया करै। यू काम ऊत माणसां के हो सैं। मेरा कहणे का मतलब जो हर लिहाज तै चौकस हो। गाम के काम करवाण खातिर किसी भी हद ताहीं चला ज्या।

- रसीले तूं के काम आवैगा। सूत कसूत आले काम तूं देख लिये। बाकी हाम संभाल लेंगे।

- तूं क्या तैं पंगे में पां दे सै छबीले? कदे बाद में न्यू कहै अक- खोट नहीं और वोट नहीं। गामां की सियासत बहुत टेढ़ी हो सै। बेशक भीतां कै कान लागे रहते हों पर के मजाल न्यू बेरा लागज्या अक फलाणी वोट किसकी सै। एक तैं एक कलाकार सैं। और एक बात बताऊं, दूर दुरहेटे के माणस वोट द देंगे पर कुछेक घर आले और अड़ौसी-पड़ौसी पर्ची ना दिया करते।

- भाई तनै दिखता नहीं गाम का हाल। चौगरदे तैं हालत खराब सैं। ईब ताहीं जितणे भी पंचायती होए, लगभग अनपढ़ां बरोबर थे। किसे नै न्यूए नहीं बेरा था अक काम के हों सैं और क्यूकर हो सैं। यू तो भला हो इस सरकार का जो गामां में पढ़े लिखे पंचायतियां का नियम बणा दिया। एक बात कहणी पड़ैगी रसीले, पिछली बार जिन गामां के सरपंच आच्छे पढ़े लिखे और चौकस थे उन नै गाम में काम खूब कराए। साफ सफाई का पूरा ख्याल राख्या और साफ सुथरे पार्क भी बणवाए।

- छबीले गलियां की साफ सफाई सबतैं जरूरी काम सै। निकासी के पानी की व्यवस्था दुरुस्त हो तैं बहुत सारी परेशानियां खुद ए समाप्त होज्या सैं। उसके बाद गाम का सचिवालय बहुत जरुरी सै जड़े गाम के लोग-लुगाई आपणे-आपणे काम आसानी तै करा सकैं। सही बात तो यो सै भाई सरकार के साथ कदम तैं कदम मिलाकै विकास कार्य कराणे हो सैं। गाम में टांग खिंचणिये भी मिलज्यांगे पर उनतै पार पाकै काम कराणे हो सैं। चौधर का बोझ बहुत घणा हो सै। बड़ी सोच भी राखणी हो सै और धैर्य भी राखणा हो सै।

- रसीले, देखता जा। जै गाम नै सेवा का मौका दे दिया तो बहुत काम करैंगे। गांव में दो तीन ई लाइब्रेरी की जरुरत सै जड़ै बैठकै बालक पढ़ लिख सकैं।

- और सुण गाम में बांदरां का खूब आतंक सै। लोग बहुत परेशान हो लिए। इनका इलाज भी करैंगे।

- छबीले एक काम क्यूं नहीं हो सकता। गाम में सरपंची की सर्वसम्मति की कोशिश करी जावै तो किसा रहै?

- भाई बहुत मुश्किल सै। इसकी वजह यो सै अक बहुत सारे कंडीडेट गाम के विकास खातिर लैक्शन कोन्या लड़ रे। एक दूसरे ठोले की मरोड़ काढण खातिर चुनाव लड़ रे सैं। उननै न्यू बेरा होणा चाहिए अक मरोड़ कै करोड़ लाग्या करैं।

- भाई जै सर्वसम्मति होज्या तैं राज्य सरकार सर्वसम्मति तै चुनी गई पंचायतां नै 11 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दे सै। इसके अलावा, सर्वसम्मति तै चुने जाने वाले सरपंच ताहीं पांच लाख रुपए तथा पंच को 50 हजार रुपए की राशि दे सै। इतणा ए नहीं सर्वसम्मति तै चुने जाने वाले जिला परिषदों के सदस्यों तथा पंचायत समितियों के सदस्यों को क्रमशः 5 लाख रुपए व 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दे सै।

- सर्वसम्मति का फायदा यू भी सै अक चुनाव खर्च बचज्या और गाम में प्रेम व भाईचारा बणा रहै। चाल बुरेआलां की पौली में चालैंगे और सवर्मसम्मति की बात करैंगे। कोशिश करण में के जा सै। साफ सुथरी और बढ़िया बात कदे करल्यो।

- मनोज प्रभाकर

फिर विकल हैं प्राण मेरे !

तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है!
जा रहे जिस पंथ से युग कल्प उसका छोर क्या है?
क्यों मुझे प्राचीन बनकर आज मेरे श्वास घेरे?
सिंधु की नि:सीमता पर लघु लहर का लास कैसा?
दीप लघु शिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा?
दे रही मेरी चिरंतनता क्षणों के साथ फेरे!
बिंबग्राहकता कणों को शलभ को चिर साधना दी,
पुलक से नभ भर धरा को कल्पनामय वेदना दी;
मत कहो हे विश्व झूठे हैं अतुल वरदान तेरे!
नभ डुबा पाया न अपनी बाढ़ में भी क्षुद्र तारे,
ढूंढ़ने करुणा मृदुल घन चीर कर तूफान हारे;
अंत के तम में बुझे क्यों आदि के अरमान मेरे।

- महादेवी वर्मा

डॉ अमित अग्रवाल, भा.प्र.से. प्रबंध निदेशक, संवाद (सूचना जन संपर्क एवं भाषा विभाग) हरियाणा द्वारा हरियाणा सरकार के लिए कमरा नं. 314, दूसरी मंजिल, लघु सचिवालय, सेक्टर-1, पंचकूला से प्रकाशित।
कार्यालय : संवाद सोसायटी एससीओ 23, पहली मंजिल, सेक्टर 7, चंडीगढ़ फोन : 0172-2723814, 2723812 email : editorsamvad@gmail.com